भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4025
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग पर अमरीकी प्रशुल्क का प्रभाव

4025. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा भारत से इस्पात के आयात पर 25 प्रतिशत प्रशुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय इस्पात उद्योग को हुई अनुमानित वित्तीय हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत से अमरीका को इस्पात का निर्यात कितनी मात्रा में किया गया है और प्रशुल्क लागू होने के बाद से निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी आई है ;

(ग) क्या सरकार भारतीय इस्पात निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और प्रशुल्क के कारण होने वाले घाटे को कम करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अमरीका के साथ किसी वार्ता, व्यापार विविधीकरण कार्यनीतियों अथवा नीतिगत हस्तक्षेपों सहित ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आधार पर मार्च, 2018 में व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 के तहत इस्पात पर 25% का अतिरिक्त प्रशुल्क लगाया। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को तैयार इस्पात निर्यात का विवरण प्रतिशत परिवर्तन के साथ नीचे दिया गया है: -

यूएसए को तैयार इस्पात का निर्यात		
वर्ष	**मात्रा (‘000 टन में)**	**%परिर्वतन**
2019-20	51	-48.4
2020-21	27	-46.7
2021-22	214	692.6
2022-23	165	-22.9
2023-24	95	-42.3
2024-25(अप्रैल-फरवरी)*	137	44.21
स्रोत:संयुक्त संयंत्र समिति(जेपीसी); *अंनतिम		

जारी........2/

भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ लगातार बातचीत जारी रखे हुए है। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अमेरिकी- भारत व्यापार को दोगुना से अधिक करके 500 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाना है, जिसे इस्पात सहित कई क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को मजबूत करके हासिल किया जाएगा।

*****